

चंडीगढ़ लंबे कनूनी संघर्ष के बाद अदालत से वसीयतनामा फर्जी करार दाँ जाने के बाद अब फरीदकोट के पूर्व महाराजा की बेटियाँ उनकी 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ले पाएंगी। यह कनूनी लड़ाई 23 साल चली। मुख्य न्यायाधिकमजिस्ट्रेट रजनीश कुमार शर्मा ने गुरुवार को हरदिर सहि बरा की बड़ी बेटी अमृत कौर के पक्ष में फैसला सुनाया था। अमृत कौर ने वसीयतनामा को चुनौती दी थी जिसने कन्यास को बैंक जमाखाते और आभूषणों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थिति फरीदकोट हाऊस, पंजाब में महल और ककिला समेत उनकी सारी संपत्तियों का केमरटेकर नयिक्त किया था।

इन संपत्तियों में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में डेरों संपत्तियाँ शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि वसीयतनामा फर्जी और मनगढ़ंत है जिससे अमृत कौर और उनकी बहन दीपदिर कौर हद्दू उत्तराधिकार कनून के तहत 20,000 हजार करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन गई हैं। महाराजा के परिवार के वकील वकिस जैन के मुताबकि अदालत ने वसीयत को अवैध करार दिया है जो 10 कजुलाई, 1982 में फर्जी तरीके से किया गया था। इस फैसले के बाद मेहरवाल खेवाजी टरस्ट भी अवैध बन गया है। महाराजा की तीन बेटियों में अमृत कौर चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में रहती हैं, दीपदिर कौर कोलकता में हैं जबकि महीपदिर कौर कुछ साल पहले शमिला में मर गईं। जब वसीयतनामा में फर्जीवाड़ा किया गया था तब सर बरा गहरे सदमे थे क्योंकि उनके कमाटर पुत्र हरमोहदिर सहि बरा मर गए थे।

कुछ नौकरों ने कुछ लोगों और वकीलों की मदद से 10 कजून, 1982 को यह वसीयतनामा लागू कराया और महाराजा की पत्नी व मां समेत उनके परिवार के अंधेरे में रखा गया। हरमोहदिर की मौत के आठ महीने बाद वसीयतनामा लागू किया गया। महाराजा के नौकरों और वकीलों ने टरस्ट बनाया और वे उसके न्यासी बन गए। अमृत कौर को इस आधार पर उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया कि उन्होंने दविंगत महाराजा की इच्छा के खिलाफ शादी की थी। दीपदिर कौर को महज 1200 रुपए प्रतिमाह के वेतनमान पर न्यास का अध्यक्ष नयिक्त किया गया जबकि महीपदिर कौर को बस 1000 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह दिया गया। बाद में अमृत कौर ने इस वसीयतनामा को चुनौती दी और कहा कि उनके पति ने ऐसा कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था।